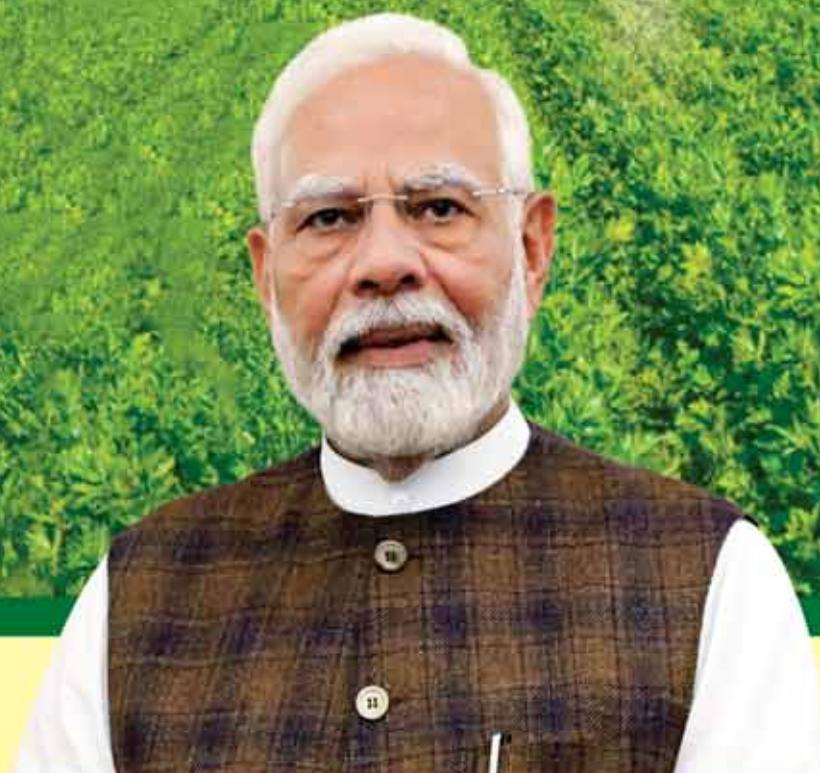


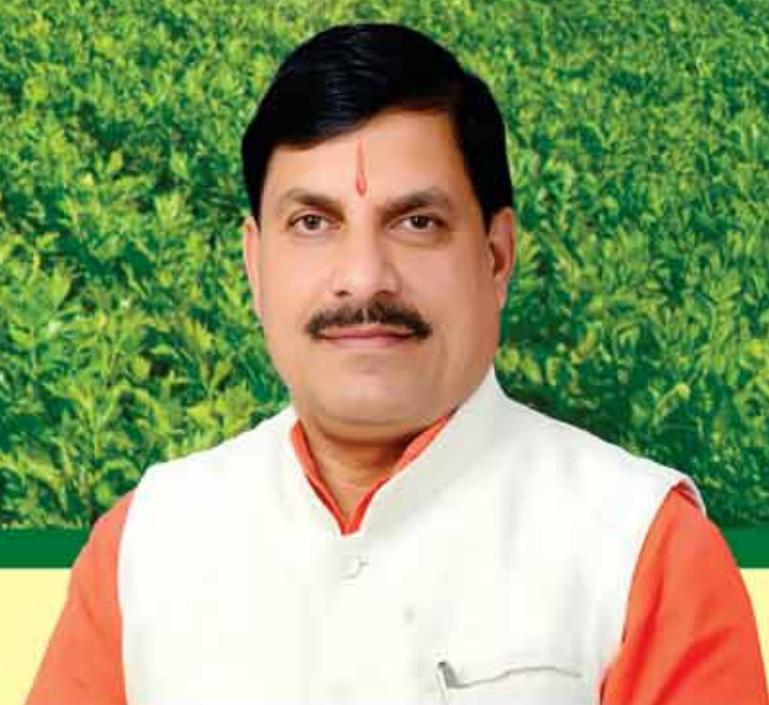
कृषि की ताकत, उद्योग का सहारा
बढ़ेगा किसान, बढ़ेगा देश हमारा



कृषि-उद्योग समागम 2025



नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री



डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

■■■■■ शुभारंभ ■■■■■

**मुख्यमंत्री
डॉ. मोहन यादव**

द्वारा

3 मई, 2025 | दोपहर 12:00 बजे
कृषि उपज मंडी ग्राउंड
सीतामऊ, मंदसौर

कृषि उद्योग समागम - किसानों के हित में नई पहल



तकनीक को प्रोत्साहन

किसान भाई-बहन एक ही मंच पर कृषि, उद्यानिकी एवं पशुपालन के, ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस युक्त आधुनिक यंत्रों एवं नवीनतम तकनीकों से परिचित होंगे।



आधुनिक आदान को बढ़ावा

सिंचाई संयंत्र, बीजों की उन्नत एवं नवीनतम किस्मों तथा वैज्ञानिक रूप से विकसित फर्टिलाइजर्स की जानकारी से भी अवगत होंगे।



कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण को नए आयाम

कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण की नवीनतम पद्धतियों, डेयरी टेक्नोलॉजी तथा मत्स्य पालन की आधुनिक तकनीकों की सटीक जानकारी एवं मार्गदर्शन।



कृषि और उद्योग की साझेदारी

कृषि एवं उद्यानिकी फसल आधारित उद्योगों से जुड़े उद्यमी, किसान उत्पादक संगठन (FPO), क्रेता-विक्रेता, निर्यातक एवं किसान संगोष्ठी के माध्यम से तलाशेंगे साझेदारी के अवसर।



किसान हित की योजनाओं में पंजीयन

फसल बीमा कंपनी, किसान क्रेडिट कार्ड एवं बैंकर्स द्वारा किसानों के साथ जानकारी साझा की जाएगी तथा किसान हित की योजनाओं में होगा किसानों का पंजीयन।

D11021/25



सीधा प्रसारण

webcast.gov.in/mp/cmevents

@Cmmadhyapradesh
@jansampark.madhya pradesh

@Cmmadhyapradesh
@jansamparkMP

JansamparkMP

#कृषि_उद्योग_समागम_MP

संपादकीय

गणना का उपयोग बेहतर हो

3A खिरकार देश में जातीय गणना का रास्ता खुल गया। यह मामला लंबे समय से सियासी द्वंद्व की भी बजह बना हुआ था। आजादी के बाद यह पहला मौका होगा जब जनगणना के दैरान जाति के आंकड़े संग्रहीत किए जाएंगे। हालांकि अनुसूचित जाति और जनजाति के आंकड़े दर्ज किए जाते हैं लेकिन व्यापक स्तर पर जातिगत आंकड़े इससे पहले 1931 की जनगणना में एकत्रित किए गए थे। इस घोषणा को दोनों प्रमुख दलों का समर्थन मिला है जो बताता है कि जाति जनगणना की राह में कोई मुश्किल नहीं है। वास्तव में 2024 के लोक सभा चुनावों में जाति जनगणना कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के सबसे प्रमुख चुनावी वादों में से एक था। चूंकि सरकार ने अगली जनगणना में जाति को दर्ज करने का निर्णय ले लिया है इसलिए अब इसके परिणामों पर चर्चा करना भी आवश्यक है। हालांकि, उससे पहले यह ध्यान देना आवश्यक है कि जल्द से जल्द जनगणना करना भी आवश्यक है। कोनिह-

जल्द से जल्द जनगणना करना मात्र आवश्यक हा कानून-डिजिटल महामारी के कारण 2020 में होने वाली दशकीय जनगणना को टाल दिया गया था लेकिन यह समझना मुश्किल है कि हालात सामान्य होने के बाद भी सरकार उसे करीब 4 साल से क्यों टालती जा रही है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों के मुताबिक 2011 में जब भारत में पिछली जनगणना हुई थी तब हमारी अर्थव्यवस्था का आकार 1.8 लाख करोड़ डॉलर था। यह संभव है कि जिस समय तक आगली जनगणना पूरी होगी या उसके परिणाम आने शुरू होंगे तब तक भारत पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बन चुका होगा। यह एकदम अलग देश होगा मगर जाति को शामिल करने की अतिरिक्त आवश्यकता को देखते हुए इसमें और देरी हो सकती है। ऐसे में यह भी संभव है कि अब जनगणना शायद 2026 के बाद ही हो और संविधान के मुताबिक संसदीय सीटों के नए परिसीमन का आधार बने। ऐसे में इसके परिणाम देश में सामाजिक विभाजन को बढ़ाने वाले साबित हो सकते हैं और उनका बहुत सर्तकता के साथ प्रबंधन करना होगा। संभव है कि कुछ राजनीतिक दल विधायिका में भी जाति आधारित आरक्षण की मांग करें। एक स्तर पर जातीय आंकड़े संग्रहीत करना तथा अन्य सामाजिक-आर्थिक आंकड़े हासिल करना उपयोगी हो सकता है क्योंकि यह नीति निर्माण में मददगार होगा। बहरहाल, जोखिम यह है कि जाति के आंकड़ों का इस्तेमाल राजनीतिक कारणों से भी किया जा सकता है। हालांकि यह तो अभी भी हो रहा है। ताजा आंकड़े इस खाई को बढ़ा सकते हैं। कम तादाद वाले जातीय समूहों को हाशिए पर धकेला जा सकता है। जाति जनगणना के अन्य संभावित परिणामों में अधिक आरक्षण की मांग भी शामिल है। वास्तव में इसकी शुरूआत ही भी चुकी है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सुझाव दिया है कि आरक्षण पर सीमा समाप्त की जानी चाहिए और निजी शैक्षणिक संस्थानों में भी कोटा लागू किया जाना चाहिए। व्यापक स्तर पर देखें तो 2025 में जाति जनगणना का इतना महत्वपूर्ण होना बताता है कि हम अभी तक कुछ बुनियादी चीजों को दुरुस्त करने में विफल रहे हैं। कई समूहों के लिए जाति जनगणना और आरक्षण में हिस्सेदारी आगे बढ़ने की एक उम्मीद है। कुछ समूह जहां इससे लाभान्वित होंगे वहीं राजनीतिक वर्ग के लिए अहम प्रश्न यह है कि क्या एक ही चीज को अलग ढंग से बांटने से देश बेहतर जगह बन सकेगा और क्या यह सबसे बाँछित हल है। इन सभी सवालों के जवाब मिलने में अभी कुछ वक्त तो लगेगा।

सुरक्षा चुनौतियों के बीच पूर्ण राज्य का प्रेरणा

प्रमोट जोरी

प हल्लामां हमल से कुछ हफ्ते पहले ही जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल होने को लेकर उम्मीद जताई थी। उस समय उन्होंने कहा था, हमें लगता है कि सही समय आ गया है, विधानसभा चुनाव हुए छ हमीने बीत चुके हैं। शाह यहां आए थे, मैंने उनसे अलग से मुलाकात की, जो अच्छी रहीज मुझे अब भी उम्मीद है कि जम्मू-कश्मीर को जल्द ही अपना राज्य का दर्जा वापस मिल जाएगा। इसके पहले विधानसभा में विपक्ष के नेता

इसका पहला विचारना मन विषद का तो
सुनील शर्मा ने कहा था कि राज्य का दर्जा
हमारा नैरेटिव है, यह भाजपा का वादा है।
अब्दुल्ला को लोगों से किए गए वादों को पूरा
करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दो हफ्ते
पहले राष्ट्रीय और खासतौर से जम्मू-कश्मीर
की राजनीति में वक़्फ़ कानून को लेकर
सरगर्मी थी, पर अब पहलगाम हमले के कारण
हालात बदले हुए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है
कि क्या इस हमले के कारण जम्मू-कश्मीर
को राज्य का दर्जा मिलने में और विलंब होगा।
क्या नेशनल कान्फ्रेंस इस मामले को उठाना
बंद कर देगी?

11 दिसंबर, 2023 को, उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 370 और 35ए को निरस्त करने को सर्वसम्मति से बरकरार खाली साथ ही केंद्र सरकार को जम्मू और कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने और सितंबर 2024 से पहले विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया। पिछले साल चुनाव भी हो गए, पर राज्य के दर्जे की बहाली नहीं हुई है। नई सरकार बनने के बाद 19 अक्टूबर, 2024 को जम्मू-कश्मीर मर्टिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का दर्जा बहाल करने का औपचारिक आग्रह भी कर दिया। उपराज्यपाल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी। अब अंतिम निर्णय केंद्र सरकार और संसद पर निर्भर है।

कुछ राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि केंद्र सरकार इस मुद्दे को धीरे-धीरे हल करना चाहती है, ताकि स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता बनी रहे। पहलगाम हमले

जाति जनगणना विभाजन का नहीं, विकास का आधार बने

■ लालत गग

हलांगम का फ्रूट एवं बरबर आतक।
घटना के बाद मोदी सरकार लगातार
पाकिस्तान को करारा जबाव देने की
तैयारी के अति जटिल एवं संवेदनशील दौर में
एकाएक जातिगत जनगणना कराने का निर्णय
लेकर न विषयकी दलों को बल्कि समूचे देश को
चौकाया एवं चमत्कृत किया है। सरकार का
यह निर्णय जितना बड़ा है, उतना ही चुनौतीपूर्ण
भी। मोदी सरकार का जातिगत जनगणना के
लिए तैयार होना सुखद और स्वागतोयग्य है।
पिछले कुछ समय से जातिगत जनगणना की
मांग बहुत जोर-शोर से हो रही थी। कुछ राज्यों
में तो भाजपा भी ऐसी जनगणना के पक्ष में
दिखी थी, पर केंद्र सरकार का रुख इस पर
बहुत साफ नहीं हो रहा था। अब अचानक ही
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में
राजनीतिक मामलों की उच्चस्तरीय कैबिनेट
समिति की बैठक में यह फैसला ले लिया गया।
बाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया
को बताया कि आगामी जनगणना में जातिगत
गणना भी शामिल रहेगी। यह कदम जहां देश
के राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों को
बदलेगा, वही सामाजिक असमानताओं को
दूर करने और वर्चित समुदायों के उत्थान के
लिए लक्षित नीतियों को लागू करने में मील का
पथर सांचित होगा।

जातिगत जनगणना 1951 वाली भारत में अंग्रेजी सत्ता ने कराई थी। भारत में जनगणना की शुरूआत अंग्रेजी हूकमत के दौर में, सन 1872 में हुई थी और 1931 तक हुई हर जनगणना में जाति से जुड़ी जानकारी को भी दर्ज किया गया। आजादी के बाद सन् 1951 में जब पहली बार जनगणना कराई गई, तो तथ्य हुआ कि अब जाति से जुड़े आंकड़े नहीं जुटाए जाएंगे। स्वतंत्र भारत में हुई जनगणनाओं में केवल अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़े डेटा को ही पब्लिश किया गया। 2011 में मनमोहन संसद ने जातिवार जनगणना कराई अवश्य, लेकिन उसमें इतनी जटिलताएं एवं विसंगतियां मिलीं कि उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। इसके बाद कुछ राज्यों ने जातियों को गिनती करने के लिए सर्वे कराए, व्यक्तिके जनगणना कराने का अधिकार केवल केंद्र को ही है। हालांकि भाजपा ने बिहार में जाति अधारित सर्वे का समर्थन किया, लेकिन जातिगत जनगणना को लेकर वह मुख्य नहीं रही। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अवश्य इसका समर्थन किया। लेकिन अब एकाएक भाजपा को जातिगत जनगणना करना अपने हित में दिखाई दिया व्यक्तिकि अपनी नीतियों एवं योजनाओं के बल पर भाजपा ने पिछड़ी जातियों और दलितों की गोलबंदी कर सत्ता का सफर आसान बनाया है जातिगत जनगणना का भारतीय राजनीति



और समाज-व्यवस्था पर व्यापक एवं दूरगामा प्रभाव पड़ेगा। कांग्रेस और कुछ क्षेत्रीय दल इसकी पुरजोर मांग करने में लगे हुए थे। सबसे ज्यादा जोर राहुल गांधी दे रहे थे, जबकि नेहरू से लेकर नरसिंह राव तक ने इसकी जरूरत नहीं समझी। यह तय है कि जातिगत जनगणना कराने के फैसले पर जहां कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दल इसका श्रेय लेना चाहेंगे, वहाँ भाजपा इसे सामाजिक न्याय एवं समता-संतुलित समाज-निर्माण केंद्रित अपनी पहल बताएगी। जाति आधारित जनगणना सामाजिक न्याय में सहायक बनेगी या नहीं, लेकिन इससे जातिवादी राजनीति के नए दरवाजे खुलेंगे एवं आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर राजनीति की धूरी बनेगा। कांग्रेस एवं विपक्षी दलों ने अपने संकीर्ण एवं स्वार्थी राजनीतिक नजरिये से यह मांग इसलिए उठाई थी ताकि इस आधार पर आगे आरक्षण के मुद्दे को गर्माया जा सके और जातीय गोलबंदी कर चुनावी फायदा लिया जा सके। लेकिन भाजपा-सरकार ने जाति जनगणना का ऐलान कर इस मुद्दे को अपनी पाली में ले लिया है। भले ही इसके आंकड़े आने के बाद आबादी के अनुपात में आरक्षण की मांग से भाजपा कैसे निपटेगी, यह बड़ी चुनौती उसके सामने है। वैसे भी इस तरह की पहल जिन राज्यों में हुई है, वहाँ भी इसे लेकर विवाद चल रहा है। ऐसे विवाद भाजपा के लिए एक नयी चुनौती बनेंगे। जाति आधारित जनगणना से भारतीय समाज के नये कोने-अंतरे-चुनौतियां सामने आयेंगी। लेकिन जातिगत जनगणना के समर्थकों का मानना है कि यह सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम हो सकता है। जनगणना में दलितों और आदिवासियों की संख्या तो गिनी जाती है और उन्हें राजनीतिक आरक्षण भी मिला हुआ है लेकिन पिछड़ी और अति पिछड़ी (ओबीसी और इबीसी) जातियों के कितने लोग देश में हैं इसकी गिनती नहीं होती है। जनगणना एक बहुत बड़ी कवायद है और अगर इसमें जातिगत गणना को भी शामिल किया जा रहा है, तो काम और भी सावधानी एवं सतर्कता से करना होगा।

हजारा जातिया हैं और उनको हजारा उप-
जातियां हैं। सबको अलग-अलग गिनने
लिए देश को अपनी डिजिटल शक्ति का
उपयोग करना पड़ेगा।

नाश्चत हो नया राजनीतिक एवं नातांगत स्थितियां समस्याएँ खड़ी होगी। अब सभी जातियों की गिनती होगी। यह गिनती मुस्लिम, ईसाई और अन्य समुदायों में भी होनी चाहिए, क्योंकि कोई दावा कुछ भी करे, जाति और उसके आधार पर विभेद सब जगह है। इससे भी ज्यादा आवश्यक, बल्कि अनिवार्य यह है कि जातिगत जनगणना जातिवाद की राजनीति का हथियार न बने और वह भारतीय समाज को है, या फिर उसने बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में चुनावी लाभ लेने के लिए ये क्रदम उठाया है। भाजपा इसके खिलाफ थी, उसने जातिगत जनगणना को देश को बांटने की कोशिश करने वाला बताया था। लेकिन एनडीए में शामिल भाजपा की ज्यादातर सहयोगी पार्टियां इसके पक्ष में हैं। जातिगत जनगणना के आंकड़े 2026 या 2027 के अंत में आएंगे और तब तक बिहार

यह जनगणना न क्या तो यह जनगणना क्या विभाजित न करने पाए। इस अंदेशे को दूर करने के कुछ ठेस उपाय होने ही चाहिए कि जाति आधारित जनगणना जातीय विभाजन का कारण न बनने पाए। यह अंदेशा इसलिए है, क्योंकि यह किसी से छिपा नहीं कि कई राजनीतिक दल खुले रूप से जाति की राजनीति करते हैं। माना जाता है कि देश की आबादी में 52 फ़ीसदी लोग पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति के हैं। ओबीसी समुदाय के नेताओं का मानना है कि इस हिसाब से उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी काफ़ी कम है। राजनीतिक दल इन समुदायों का समर्थन हासिल करने के लिए जाति जनगणना का समर्थन कर रहे हैं।

भारत में जाति जनगणना आजादी के बाद रुकी, पर अब सामाजिक न्याय, नीतिगत सुधार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए इसकी जरूरत महसूस की जा रही है। पारदर्शिता और सावधानी से किया गया यह कदम समावेशी विकास का आधार बन सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जाति आधारित जनगणना को एक समतामूलक समाज निर्माण के दृष्टिकोण से समर्थन देने के संकेत दिए हैं। संघ के अधिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने कहा कि यह संवेदनशील मामला है और इसका इस्तेमाल राजनीतिक या चुनावी उद्देश्यों के लिए नहीं बल्कि पिछड़ रहे समुदाय और जातियों के कल्याण के लिए होना चाहिए। जाति जनगणना के आंकड़े प्रस्तुत होने से 2027 के उत्तरान आदेश जारी रखा जायेगा और यूपी के चुनाव हो चुके होंगे। इसलिए इसका चुनावी लाभ लेने की बात सही नहीं है। वैसे भी भाजपा ने हाल के वर्षों में पिछड़े और दलितों समुदाय को अपने साथ जोड़ने में कामयाबी हासिल की है। भाजपा इस जातिगत गणना से ये भी दिखाना चाहती है कि पिछड़ों के एक-आध समुदाय को छोड़ दें तो ओबीसी समुदाय का बड़ा हिस्सा उसके साथ है। वैसे तो विभिन्न राजनीतिक दल अमुक-अमुक जातियों का नेतृत्व करने के लिए केवल जाने ही नहीं जाते, बल्कि ऐसा दावा भी करते हैं। इसलिये जाति आधारित जनगणना का लाभ है तो हानि भी है। इससे बेहतर और कुछ नहीं कि जातिगत जनगणना वर्चितों-पिछड़ों के उत्थान में सहायक बने, लेकिन यदि वह विभाजन को बल देती है और देश की एक जुटता प्रभावित करती है तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं होगा। जनगणना के आंकड़े सरकार और जनता के लिए खुले और पारदर्शी होने चाहिए, ताकि सामाजिक संबंधों, आर्थिक अवसरों और राजनीतिक गतिशीलता की नई एवं समानतामूलक दिशाएं उद्घाटित हो सके और भारतीय समाज की विविधता की एक व्यापक सकारात्मक तस्वीर प्रस्तुत की जा सके। कोई भी आंकड़ा तभी सराहनीय है, जब उससे विकास तेज करने में मदद मिलती हो, एक समतामूलक एवं संतुलित समाज की संरचना को बल मिलता हो।

(साभारः यह लेखक के निजी विचार हैं)

लेने से मनस्थ आपने

शत्रु के समान हो जाता है।
- बेकन

1

आज का इतिहास

- 1964 - जगान के नवाय मीर कासिम को अंग्रेजों ने हराया।
 - 1913 - पहली भारतीय फीचर फिल्म राजा हरिश्चन्द्र प्रदर्शित हुई।
 - 1919 - अमानुल्ला खान द्वारा ब्रिटिश भारत पर आक्रमण जिससे ऐंग्लो-अफगान युद्ध की शुरूआत हुई।
 - 1989 - देश के पहले 50 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का हरियाणा में शुभारंभ।
 - 1993 - संयुक्त राष्ट्र ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की।
 - 1998 - यूरो को यूरोपीय मुद्रा के रूप में स्वीकार करने का यूरोपीय नेताओं का ऐतिहासिक फैसला।
 - 2002 - अमेरिकी मीडिया ने परवेज मुशर्रफ के जनमत संग्रह का राननाक जनना।
 - 2003 - आस्ट्रेलिया के स्टीव वॉटेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने।
 - 2006 - पाकिस्तान और ईरान ने 3 देशों की गैस पाइप लाइन परियोजना से भारत को अलग करने के उद्देश्य से द्विपक्षीय गैस पाइप लाइन करार पर दस्तखत किए।
 - - शिक्षाविद कमलेश पटेल को ब्रिटेन के हाउस आफ लार्ड्स में गैर दलीय पीयर नियुक्त किया गया।
 - 2008 - टाटा स्टील लिमिटेड को ब्रिटेन में कोयला खनन करने का पहला लाइसेंस प्राप्त हुआ।
 - 2013 - चीन में डायनासोर का लगभग 16 करोड़ साल पुराना जीवाश्म मिला।

निराना यल रही लड़ाई !



(साभार : लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

-कृष्णन्द्र रा-

तु डाल डाल, मै पात पात ।
 चल रहा फिलहाल ॥
 कौन सही कौन गलत ।
 बड़ा है सवाल ॥
 है लड़ाई जारी ।
 सबकी अपनी जंग ॥
 है कोई नाराज ।
 किसी को उमंग ॥
 कोट्ट और सरकार में ।
 चल रही लड़ाई ॥
 कौन पड़ेगा भारी ?
 है वो घड़ी आई ॥
 अपने अपने ढंग से ।
 हैं सबके प्रहार ॥
 सबकी अपनी हद ।
 हैं दूसरे दूसरे ॥

